ऊर्जा क्रांति की अग्रणी बनीं महिलाएं

1.51 करोड़ घरों में पहुंचा पाइप्ड नेचुरल गैस

99% आबादी को कवर कर रहा सिटी

नई दिल्ली. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का ऊर्जा क्षेत्र तेजी से बदल रहा है, जिससे स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल के जरिए महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना- अब तक 10.33 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिससे उन्हें रसोई के धुएं से मुक्ति मिली है और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है.

पाइप्ड नेचुरल गैस कवरेज- देश में 1.51 करोड़ घरों तक पीएनजी की सुविधा पहुंच चुकी है.

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन- सीजीडी नेटवर्क अब भारत के 96 प्रतिशत भूभाग और 99% जनसंख्या को कवर करता है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच आसान हुई है.

महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका- महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं. वे बायोगैस संयंत्र, रिटेल फ्यूल आउटलेट्स और एलपीजी वितरण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण लेकर काम कर रही हैं.

कम्प्रेस्ड बायोगैस खरीद- वित्त वर्ष 2024-25 में 42,800 टन सीबीजी की खरीद की गई है, जो हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है.

ऊर्जा आत्मनिर्भरता- भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है. सरकार ने 99% नो-गो क्षेत्रों को हरी झंडी दे दी है और 10 लाख वर्ग किलोमीटर अपतटीय क्षेत्र तेल और गैस खोज के लिए खोल दिया गया है. ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के तहत घरेलू और विदेशी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है.पुरी ने जोर देकर कहा, आज की भारतीय महिला केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि देश के ऊर्जा भविष्य को आकार देने वाली नेतृत्वकर्ता बन चुकी है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की ये पहलें न केवल स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं.

उज्ज्वला योजना में 13 लाख निष्क्रिय उपभोक्ता

नयी दिल्ली, 28 जुलाई (वार्ता) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के देश में 10 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं. इनमें से 1.3 प्रतिशत यानी 13 लाख से अधिक ने कनेक्शन लेने के बाद एक भी रीफिल नहीं कराया है.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उज्ज्वला योजना के निष्क्रिय कनेक्शनों की पहचान इन आँकड़ों के आधार पर की जा सकती है कि कितने उपभोक्ताओं ने एक बार भी रीफिल नहीं कराया है. उन्होंने बताया कि 01 जुलाई 2025 तक उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं की संख्या 10 करोड़ 33 लाख है. इनमें निष्क्रिय उपभोक्ता 1.3 प्रतिशत थे जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद से एक भी बुकिंग नहीं करायी है.

आरबीआई की जी-सेक नीलामी सफल

2028 और 2035 में परिपक्व होने वाली दो प्रतिभूतियों की नीलामी

6,000 करोड़ और ?30,000 करोड़ की पूरी राशि सब्सक्राइब

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को 36,000 करोड़ की दो सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न की. दोनों नीलामियां पूरी तरह से सब्सक्राइब हुईं, जो सरकारी बॉन्डों के लिए मजबूत मांग को उजागर करती हैं.

आरबीआई द्वारा जारी विस्तृत नीलामी परिणामों के अनुसार, नीलाम की गई दो प्रतिभूतियां 2028 में परिपक्व होने वाली 5.91 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति (6,000 करोड़) और 2035 में परिपक्व होने वाली 6.33 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति थीं.

2028 के 5.91 प्रतिशत जी-सेक के लिए नीलामी में 98 प्रतिभागियों से 24,453 करोड़ की प्रतिस्पर्धी बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि 2035 के 6.33 प्रतिशत जी-सेक के लिए 402 बोलीदाताओं से 74,694 करोड़ की बोलियां मिलीं. मूल्यांकन के बाद, आरबीआई ने 2028 बॉन्ड के लिए 5,998.13 करोड़ और 2035 बॉन्ड के लिए ?29,947.86 करोड़ की प्रतिस्पर्धी बोलियां स्वीकार कीं. गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां भी पूरी तरह से स्वीकार की गईं. जो क्रमशः 1.86 करोड़ और 52.13 करोड़ थीं.

> दोनों प्रतिभूतियों को प्राथमिक डीलरों से पूर्ण अंडरराइटिंग समर्थन मिला. 2028 बॉन्ड के लिए ?6,000 करोड़ और 2035 बॉन्ड के लिए ?30,000 करोड़ की पूरी अधिसूचित राशि को अंडरराइट किया गया और स्वीकार किया गया. भारित औसत यील्ड क्रमशः 5.7986 प्रतिशत और 6.3325 प्रतिशत पर मामूली रूप से कम थी, जो निवेशकों की थोड़ी कम रिटर्न स्वीकार करने की इच्छा को दर्शाती है, जो सरकारी प्रतिभूतियों में मजबूत विश्वास का संकेत है.

वीरेंद्र गर्ग ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की

रोहतक, 28 जुलाई. प्रतिष्ठित समाजसेवी और पंजाबी बाग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के उप प्रधान वीरेंद्र गर्ग ने 20 जुलाई को संपन्न हुए वैश्य एजुकेशन सोसायटी रोहतक के चुनाव में कोलेजियम नंबर ग्यारह से भारी बहुमत से जीत दर्ज की.

उन्हें 69 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी मोहन गुप्ता को केवल 1 मत प्राप्त हुआ. कोलेजियम नंबर 11 में पूर्वी तथा पश्चिम पंजाबी बाग सहित विभिन्न क्षेत्रों के कुल 170 मतदाता शामिल थे, जिनमें से 70 मतदाताओं ने रोहतक जाकर मतदान किया.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित वैश्य एजुकेशन सोसायटी रोहतक में 81 एकड़ भूमि में फैली है, जो नर्सरी से इंजीनियरिंग, एमबीए और पीएचडी तक की शिक्षा प्रदान करती है. इसके लगभग 16,000 सदस्य हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में हैं. चुनाव के लिए सदस्यों को 105 कोलेजियम में विभाजित किया गया है, जो 105 प्रतिनिधि चुनते हैं. ये प्रतिनिधि 21 सदस्यीय कार्यसमिति का गठन करते हैं, जो संस्था का संचालन करती है. लाखों विद्यार्थियों ने इस सोसायटी से शिक्षा प्राप्त कर देश और समाज में योगदान दिया है.

लगातार दूसरे दिन बिकवाली, सेंसेक्स 81 हजार अंक से नीचे उतरा

मुंबई, 28 जुलाई (वार्ता) विदेशी निवेशकों की बिकवाली और रुपये में जारी गिरावट से घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही.प्रमुख सूचकांकों में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 572.07 अंक यानी 0.70 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,891.02 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 156.10 अंक (0.63 फीसदी) टूटकर 24,680.90 अंक पर आ गया. गिरावट में खुलने के बावजूद शुरुआती कारोबार में कुछ समय के लिए शेयर बाजार हरे निशान में रहे थे, लेकिन दोपहर बाद सूचकांक तेजी से गिरे. सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 23 के शेयर गिरावट में और शेष सात के बढ़त के साथ बंद हुए.

पहली तिमाही में कंपनियों की धीमी रफ्तार

ऊर्जा और कोयला क्षेत्र में मांग घटी, इस्पात क्षेत्र स्थिर

मानसून और भू-राजनीतिक तनाव ने डाला असर

नयी दिल्ली, 28 जुलाई (वार्ता) ऊर्जा, कोयला, सूचना प्रौद्योगिकी और इस्पात क्षेत्रों के सुस्त प्रदर्शन के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय कंपनियों के प्रदर्शन में गिरावट आयी है और उनकी राजस्व वृद्धि दर घटकर चार से छह प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है.

बाजार अध्ययन एवं निवेश सलाह कंपनी क्रिसिल की सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में 600 से ज्यादा कंपनियों के जारी वित्तीय परिणामों के अध्ययन के आधार पर यह बात कही गयी है. इन 600 कंपनियों के कुल राजस्व में एक-तिहाई का योगदान इन्हीं चारों क्षेत्रों का है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की कंपनियों के औसत राजस्व में लगभग सात प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. इस साल इसके चार से छह प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है. इसी प्रकार कर पूर्व लाभ (एबिटडा) भी साल-दर-साल आधार पर चार प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है.

हालांकि आईटी सेवा, ऑटोमोबाइल, रोजगार के उपभोक्ता उत्पाद और फार्मा कंपनियों के दबाव में राजस्व के मुकाबले इबिटडा के अनुपात में 10 से 30 आधार अंकों की कमी आने का अनुमान है.

क्रिसिल इंटेलिजेंस के निदेशक पुशन शर्मा ने कहा कि मानसून के जल्दी आने और जारी भू-राजनैतिक तनावों का कुछ सेक्टरों पर अप्रैल-जून तिमाही में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है. बारिश के कारण तापमान कम रहने से बिजली की मांग में कमी आती है. इससे एक साल पहले के मुकाबले ऊर्जा क्षेत्र के राजस्व में आठ प्रतिशत की गिरावट आयी है. इससे कोयले की मांग में भी दो-तीन प्रतिशत की कमी आयी है.

उन्होंने बताया कि भू-राजनैतिक अनिश्चितता के कारण आईटी सेवा क्षेत्र की राजस्व वृद्धि दर लगभग स्थिर रही है. आयात शुल्क की चिंता के कारण परियोजनाओं में देरी हुई है. क्रिसिल की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहली तिमाही में स्टील सेक्टर का राजस्व एक से तीन प्रतिशत बढ़ने की संभावना है. ऑटोमोबाइल क्षेत्र के राजस्व में चार प्रतिशत और निर्माण क्षेत्र का छह प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है.

वहीं, सुस्ती के बीच फार्मा क्षेत्र, दूरसंचार सेवा, संगठित रिटेल, एल्युमीनियम और विमान सेवा क्षेत्र की कंपनियों का राजस्व बढ़ने की उम्मीद है. फार्मा क्षेत्र का राजस्व 9-11 प्रतिशत, दूरसंचार सेवा क्षेत्र का 12 प्रतिशत, एल्युमीनियम कंपनियों का लगभग 23 प्रतिशत और विमान सेवा क्षेत्र का 15 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है.

विज्ञप्ति के अनुसार, इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों से मांग आने से एफएमसीजी सेक्टर की बिक्री में पहली तिमाही में चार से पांच प्रतिशत, सीमेंट में तीन से चार प्रतिशत और स्टील में सात से नौ प्रतिशत की बढ़त का अनुमान है.

> उन्होंने बताया कि भू-राजनैतिक अनिश्चितता के कारण आईटी सेवा क्षेत्र की राजस्व वृद्धि दर लगभग स्थिर रही है. आयात शुल्क की चिंता के कारण परियोजनाओं में देरी हुई है. क्रिसिल की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहली तिमाही में स्टील सेक्टर का राजस्व एक से तीन प्रतिशत बढ़ने की संभावना है. ऑटोमोबाइल क्षेत्र के राजस्व में चार प्रतिशत और निर्माण क्षेत्र का छह प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है.

दुर्लभ खनिजों में भारत की खोज तेज

नई दिल्ली, 28 जुलाई. चीन द्वारा रेयर अर्थ मिनरल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद, भारत में इन दुर्लभ खनिजों की खोज में राज्यों की सक्रिय भागीदारी काफी उत्साहजनक है.

इससे देश में क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है, साथ ही भारत इन महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भर बन सकता है. यह जानकारी सोमवार को जारी भारतीय स्टेट बैंक की एक शोध रिपोर्ट में दी गई. रिपोर्ट के अनुसार, देश में बीते चार वर्षों में रेयर अर्थ मिनरल का औसत आयात 249 मिलियन डॉलर रहा है. वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में यह 291 मिलियन डॉलर था, जो कि चार वर्षों में सबसे अधिक है.

भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्य कांति घोष ने कहा, हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि प्रतिबंध से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में परिवहन उपकरण, बेसिक मेटल, मशीनरी, निर्माण और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं. इससे घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों प्रभावित होंगे.

महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के उद्देश्य से सरकार ने 2025-31 की अवधि के लिए 18,000 करोड़ रुपये के कुल आवंटन के साथ एक मजबूत बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (एनसीएमएम) को शुरू किया है. रिपोर्ट में बताया गया कि महत्वपूर्ण खनिजों में घरेलू मूल्य-श्रृंखला निर्माण के लिए राज्य सरकार की भागीदारी आवश्यक होगी. कई राज्यों ने अन्वेषण लाइसेंस (ईएल) की नीलामी के लिए निविदाएं जारी कर दी हैं. ओडिशा सरकार की औद्योगिक नीति संकल्प 2022, इस नीति के तहत रेयर अर्थ मिनरल पर आधारित मूल्यवर्धित उत्पादों को एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में मान्यता देती है.

भारत की सबसे सुरक्षित ऑल-व्हील ड्राइव ईवी

हैरियर.ईवी लॉन्च की, शुरुआती कीमत रुपए 21.49 लाख से शुरू

नई दिल्ली, 28 जुलाई. भारत की सबसे बड़ी 4-व्हीलर ईवी निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने आज हैरियर.ईवी क्वाड व्हील ड्राइव के बहुप्रतीक्षित वेरिएंट्स की कीमतों की घोषणा की, भारत की सबसे सुरक्षित और सबसे पावरफुल ऑल-व्हील ड्राइव एसयूवी क्वाड व्हील ड्राइव की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 28.99 लाख रखी गई है. हैरियर ईवी में Dual Motor Technology है, जो फ्रंट में 158 PS और रियर में 238 PS की पावर और 504 एनएम का टॉर्क प्रदान करती है. यह एसयूवी सिर्फ 6.3 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसमें बूस्ट मोड और ऑफ-रोड असिस्ट जैसे फीचर्स हैं. इसके अलावा, में 627 किमी की रेंज, 15 मिनट में 250 किमी की रेंज जोड़ने वाला फास्ट चार्जिंग और लाइफटाइम बैटरी वारंटी जैसे फीचर्स भी हैं. इस एसयूवी ने भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है, जो ग्राहकों की सुरक्षा को प्रदर्शित करती है. श्री विपिन सिंह रीजनल मैनेजर सेल्स एवं श्री विशाल जौहरी मैनेजिंग डायरेक्टर वरेण्यम मोटर कार ने हैरियर.ईवी इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स में उपलब्ध शानदार डिज़ाइन और बेहतरीन फीचर्स के साथ, डिज़ाइन, सुरक्षा और नए मानकों की सराहना की.

भारत का कोयला उत्पादन 1 अरब टन के पार

कोल इंडिया ने अकेले किया 78.10 करोड़ टन उत्पादन

2029-30 तक 1.5 अरब टन उत्पादन का लक्ष्य तय

नई दिल्ली, 28 जुलाई. भारत का कुल कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में एक अरब टन के आंकड़े को पार कर गया है. सरकार ने संसद में बताया कि देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में एक अरब टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में जानकारी दी कि कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 में 78.10 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया. देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन से पूरी होती है. कोयले के आयात में मुख्य रूप से कोकिंग कोल और उच्च श्रेणी के नॉन-कोकिंग कोल शामिल हैं, जिनका घरेलू उत्पादन कम भंडार या अनुपलब्धता के कारण सीमित है.

> **भविष्य के लक्ष्य और सरकार की पहलें**
>
> स्वदेशी स्रोतों के माध्यम से कोयले की भविष्य की मांग को पूरा करने और अनावश्यक आयात को कम करने के लिए, अगले कुछ वर्षों में घरेलू कोयला उत्पादन में सालाना 6-7 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो 2029-30 तक लगभग 1.5 बिलियन टन तक पहुंच जाएगा. वर्ष 2024-25 में देश में कुल घरेलू कोयला उत्पादन 104.76 करोड़ टन रहा, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 99.78 करोड़ टन की तुलना में लगभग 4.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और देश में कोयले के अनावश्यक आयात को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं. इनमें प्रमुख पहलें शामिल हैं- सिंगल विंडो क्लीयरेंस-प्रक्रियाओं को सरल बनाना.

खरीफ रकबा तेजी से बढ़ा

नयी दिल्ली, 28 जुलाई (वार्ता) देश में मानसून की अच्छी स्थिति और जलाशयों में भरपूर पानी जमा होने के कारण खरीफ का रकबा बेहतर बना हुआ है. मासिक आर्थिक सर्वेक्षण 2025 नाम से जारी रिपोर्ट के अनुसार 27 जुलाई तक, देश में दीर्घावधि औसत से लगभग आठ फीसदी अधिक बारिश हुई है और देश के लगभग 78 प्रतिशत भाग में सामान्य या अधिक बारिश हुयी है. यही नहीं इस साल 17 जुलाई तक के डेटा के अनुसार देश के 161 महत्वपूर्ण जलाशयों में कुल पानी पिछले साल के स्तर से लगभग 1.91 गुना और पिछले दस वर्षों के औसत से 1.70 गुना अधिक है. देश में खरीफ की भरपूर पैदावार के लिए यह अच्छा संकेत माना जा रहा है.

केनरा बैंक भारत सरकार का उपक्रम **Canara Bank** A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर - 562002

क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 0731-2573816

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **केनरा बैंक, इंदौर** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन **अधिनियम** 2002 की धारा के अंतर्गत, सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) **अधिनियम 2002 का अधिनियम संख्यांक 54** के साथ पठित, **सेक्शन 13 (12) नियम 3** के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को नोटिस जारी कर ऋणियों को नोटिस की तारीख / नोटिस प्राप्ति को तारीख से **60 दिन** के अंदर उक्त खाते के सामने दर्शाई गई राशि अदा करने के लिए कहा था। ऋणी उक्त राशि चुकाने में असफल रहा है अत: ऋणियों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट के सेक्शन **13 (4)** उक्त एक्ट के साथ पठित उक्त रूल्स के नियम **9** के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित संपत्ति का कब्जा उक्त खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को ले लिया है। एतद् द्वारा ऋणियों को विशेष एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि उक्त संपत्ति विषयक कोई संव्यवहार न करें ऐसा कोई भी संव्यवहार वसूल की जाने वाली उल्लेखित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्चो हेतु **केनरा बैंक, इंदौर** के प्रभार के अधीन रहेगा।

क्रं.	शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	ऋणी/जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग नोटिस की बकाया राशि (₹)	मांग नोटिस की दिनांक / कब्जा लेने/चस्पा करने की दिनांक
1	खण्डवा शाखा 8595058017	मेसर्स पलक वर्मा रेसीडेन्सी एण्ड बिल्डर्स, प्रोप्राईटर श्रीमती आरती वर्मा एवं श्रीमती आरती वर्मा पति सेवकराम वर्मा	लेआउट प्लाट नं. 79, प्लाट नं. 13, कर्मवीर सिटी, आनंद नगर, वार्ड नं. 50, शीट नं. 04 पर स्थित रहवासी मकान मालिपुरा, खण्डवा (म.प्र.), **क्षेत्रफल:** 900 वर्गफीट, **मालिक:** श्रीमती आरती वर्मा पति सेवकराम वर्मा, **सीमाएं: उत्तर:** कॉलोनी का प्लाट नं. 78, **दक्षिण:** कॉलोनी का प्लाट नं. 80, **पूर्व:** कॉलोनी की सड़क, **पश्चिम:** कॉलोनी का प्लाट नं. 69	25,23,704.57 + दिनांक 16.05.2025 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चें	19.05.2025 / 25.07.2025

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 29.07.2025 प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

जलयंत्रालय एवं ड्रेनेज विभाग

निविदा सूचना

विज्ञप्ति क्रमांक: 43 दिनांक: 25.07.2025

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

ग्रुप क्र.	1. टेंडर क्र. 2. जारी दिनांक	कार्य का नाम	1. कार्य की समयावधि 2. लागत	1. निविदा प्रपत्र का मूल्य 2. ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
01	2025_UAD_439889 25.07.2025	झोन क्र. 19 वार्ड क्र. 50 के अंतर्गत आँचल नगर स्थित म.नं. 307 से मेनरोड तक ड्रेनेज लाईन डालना।	3 माह ₹3,63,853/-	₹2,000/- ₹3,700/-	11-08-2025 (शाम 06:00 बजे तक) 12-08-2025
02	2025_UAD_439891 25.07.2025	झोन क्र. 09 वार्ड क्र. 46 के अंतर्गत पंचम की फेल स्थित पालिवाल वाली गली में एवं आसपास की गलियों के क्षतिग्रस्त ड्रेनेज लाईन के स्थान पर नवीन ड्रेनेज लाईन डालने बाबद।	3 माह ₹9,14,416/-	₹2000/- ₹9,200/-	11-08-2025 (शाम 06:00 बजे तक) 12-08-2025
03	2025_UAD_439892 25.07.2025	झोन क्र. 13 वार्ड क्र. 78 के अंतर्गत इन्द्रजीत नगर गली नं. 03 व 04 में ड्रेनेज लाईन डालने बाबद।	3 माह ₹5,83,054/-	₹2000/- ₹5,900/-	11-08-2025 (शाम 06:00 बजे तक) 12-08-2025
04	2025_UAD_439893 25.07.2025	झोन क्र. 12 वार्ड क्र. 66 के अंतर्गत पलसीकर आश्रम स्थल में क्षतिग्रस्त ड्रेनेज लाईन के स्थान पर नवीन ड्रेनेज लाईन डालना।	2 माह ₹1,81,497/-	₹1,000/- ₹3,700/-	11-08-2025 (शाम 06:00 बजे तक) 12-08-2025
05	2025_UAD_439894 25.07.2025	झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 43 न्यू पलासिया व ओल्ड पलासिया स्थित होलकरकालीन पुरानी गहरी सीवर लाईन के जर्जर व क्षतिग्रस्त चेम्बर पुनः निर्माण करना। (चतुर्थ बार निविदा आमंत्रण)	6 माह ₹22,05,838/-	₹5,000/- ₹16,600/-	11-08-2025 (शाम 06:00 बजे तक) 12-08-2025
06	2025_UAD_439895 25.07.2025	झोन क्र. 19 वार्ड क्र. 50 के अंतर्गत ग्रेटर बृजेश्वरी म.नं. 571 से मुख्यमार्ग तक ड्रेनेज लाईन डालना। (महापौर निधि) (द्वितीय बार निविदा आमंत्रण)	4 माह ₹11,61,000/-	₹2,000/- ₹8,800/-	11-08-2025 (शाम 06:00 बजे तक) 12-08-2025
07	2025_UAD_439896 25.07.2025	झोन क्र. 19 वार्ड क्र. 50 के अंतर्गत ग्रेटर बृजेश्वरी म.नं. 571 से मुख्यमार्ग तक ड्रेनेज लाईन डालना। (महापौर निधि) (द्वितीय बार निविदा आमंत्रण)	4 माह ₹13,70,125/-	₹2,000/- ₹10,300/-	11-08-2025 (शाम 06:00 बजे तक) 12-08-2025

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

कार्यपालन यंत्री
जलयंत्रालय एवं ड्रेनेज विभाग
नगर पालिक निगम, इन्दौर

तन और मन में तालमेल नहीं बिठा पा रहे कांग्रेसी एमएलए

पटना. विधान सभा चुनाव की तैयारी शुरु हो चुकी है. पार्टी और उनके विधायक भी टिकट की सेटिंग में जुट गए हैं. कांग्रेस में भी यही हालात हैं. लेकिन कांग्रेस के कई विधायक पार्टी को लेकर अपने तन और मन के बीच मेल नहीं बिठा पा रहे हैं. हम इसलिए ऐसा कह रहे क्योंकि बिहार विधान सभा से जो तस्वीर आ रही है वो कुछ ऐसी ही हालात बयां कर रही है. पार्टी के कई विधायक कहने के लिए तो कांग्रेस के साथ हैं लेकिन उनकी एक्टिविटी बता रही है कि उनके मन में काफी कुछ चल रहा है और वो सही मौके की तलाश में हैं. विधान सभा में इन दिनों मतदाता विशेष गहन पुनर्रीक्षण को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है.

OFFICE OF UJJAIN DEVELOPMENT AUTHORITY

Pradhikaran Bhawan, Bharatpuri Administrative Zone. Dewas Road, Ujjain 456010

email- udaujjain@gmail.com, website: www.udaujjain.org

NOTICE INVITING TENDER

Online percentage rate bids for the following works are invited from registered contractors and Firms of repute fulfilling registration criteria, Tender documents can be purchased from website https://www.mptenders.gov.in. Help manual to the contractors can be seen on the portal of e-procurement system.

Time for completion - 18 Months including rainy season And Category of Contractor-Centralised mp pwd Registration

NIT No. & Date	Tender ID	Name of work	Probable amount of contract (Rs.)	Earnest money (Rs.)	Cost of tender form+ GST (Rs.)
25/70 18/7/2025	2025_DTCP_439065_1	Constructiion of 4 Lane 24 M wide CC Road from Karkraj Parking to bhukhimata.	10.71.25.264/-	1000000/-	35400/-
25/71 22/7/2025	2025_DTCP_439369_1	Construction of Proposed Road from Piplinaka to Bhairvgarh Jail road Chouraha, 6 Lane, 45 M Width, Lenth 2000M	37.40,36,088/-	1870180/-	59000/-
25/72 22/7/2025	2025_DTCP_439398_1	Construction of Proposed Road from Piplinaka to Gadkalika, Okhleshwar Shamshan Ghat, 45 M Width, Length 1910M,	37,58.77,395/-	1879390/-	59000/-

(KULDEEP RAGHUWANSHI)
Executive Engineer.
UDA, Ujjain